

taking over these mills and rehabilitating them on a proper footing so that the cloth production may go up and employees may get employment ?

MR. SPEAKER : It is all information and suggestions. Still it is a supplementary.

SHRI R. K. KHADILKAR : About sixty mills are taken over and some of them are relief undertakings.

So far as cloth production and other aspects are concerned, he should address this question to the Foreign Trade Minister.

श्री कृष्ण चन्द पाडे : मैं श्रम मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि किम् प्रदेश में अधिक मिलें बन्द हुई हैं या बन्द होने की आशंका है ? क्या उत्तर प्रदेश में अधिक संख्या में चीनी मिलें और सूत की मिलें बन्द हैं ? यदि हाँ, तो कारण क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहते हैं कि वह इस को टेबल पर रख देंगे ।

SHRI THA KIRUTTINAN : Is it a fact that many State Governments are not able to re-open closed mills only because the Central Government has not permitted them and also the Government of India has not sanctioned the 51 per cent of the shares ?

SHRI R. K. KHADILKAR : It is not a correct statement. If preliminary investigation proves that it is likely to be viable and could be run, certainly, the State Government encourage reopening of the mills. In the case of Tamilnadu, one or two mills were reopened. Government has borne its share of the financial responsibility.

श्री हुकम चन्द कछवाय : जो उद्योग बन्द हो रहे हैं, वे अधिकांशतः पुराने उद्योग हैं । उनके मालिक उन उद्योगों के नाम से सरकार से ऋण लेते हैं और उम रुपये को दूसरे उद्योगों में लगा देते हैं । इस कारण वे उद्योग बन्द हो रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि उद्योगों को इस प्रकार बन्द होने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ।

SHRI R. K. KHADILKAR : Quite a few industries which are closed are due to mismanagement, or as the Member suggested, because the management or the proprietors

had taken the cream out of the concern and then left it there as sick unit or unit not in a position to function, etc. That is true.

MR. SPEAKER : Question 496, Shri Venkatasubbaiah—absent. Question 497, Shri Baladhandayutham—absent. Question 498, Shri Varkey George—absent.

All the three Members are absent ; they are preventing the chance for the other Members. वे प्रश्न कर देते हैं, लेकिन हाउम में मौजूद नहीं होते ।

SHRI PILLOO MODY : Let us put them all in jail !

ए० सी० सी०, नौरोजाबाद (मध्य प्रदेश) स्थित कोयला खान का बन्द हो जाना

*499. श्री धनशाह प्रधान : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के शाहडौल जिले में नौरोजाबाद स्थित ए० सी० सी० कोयला खान बन्द कर दी गई है ; और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या वहाँ पर काम करने वाले लगभग 6,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं ; और

(ग) इन 6,000 कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI BALGOVIND VERMA) :

(a) to (c). Due to outbreak of fire in the mine and to ensure the safety of the employees, the Mines Inspectorate ordered stoppage of normal working of the mine with effect from the 28th February, 1972. About 1300 workmen have been affected. Government is exploring ways and means to restart the functioning of the Colliery. It is expected that work in one of the inclines will be resumed shortly and about 500 workers will be employed. In the meantime the possibilities of finding jobs for the affected workmen in neighbouring colliery of

the same management are being explored. The question of granting financial assistance to the workmen by way of advances etc., is also being looked into.

श्री धनशाह प्रधान : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब 28 फरवरी को नौरोजाबाद स्थित ए० सी० सी० कोयला खान में आग लगी, तो इंस्पेक्टर वगैरह मारा माइनिंग स्टाफ क्या कर रहा था और क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सारे देश में कोयला खानों में जो आग लगती रहती है, उसकी रोक-थाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : सरकार हमेशा यह प्रयत्न करती है कि कोयला खानों में हर तरह की सावधानी बरती जाये। इंस्पेक्टर वहाँ बराबर जाकर निरीक्षण करने रहते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि कोयले में गैस उत्पन्न होती है और आटोमेटिक आग लग जाती है—आग कोई लगाना नहीं है। कोशिश की जाती है कि आग न लगने पाये। हमलिये किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री धनशाह प्रधान : नौरोजाबाद स्थित ए० सी० सी० कोयला खान के अलावा जुहना कोलियरी आदि जितनी भी कोयला खानें हैं, वहाँ छत को रोकने के लिए लकड़ी लगाई जाती है, वहाँ सब जगह गन्दगी पड़ी रहती है और बीड़ी-सिगरेट पी जाती है। इन कारणों से आग लगती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : सरकार ने कोयला खानों में बीड़ी-सिगरेट पीना बिल्कुल बन्द कर रखा है। कोयले से भी आग न लगे, इसलिए उसको पानी से तर रखा जाता है। अगर इसके बावजूद कहीं आग लगती है, तो उसकी एन्क्वायरी कराई जाती है और कोई दोषी पाया जाता है, तो उसको दंडित किया जाता है।

श्री राम नारायण शर्मा : मन्त्री महोदय ने बताया है कि ए० सी० सी० की दूसरी कोलियरी

में कर्मचारियों को काम देने की कोशिश की जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह कौन सी कोलियरी है। क्या माइनिंग डिपार्टमेंट या मीनेजमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से गैस पैदा हुई और इनमें आग लगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट ने कर्मचारियों को ले-आफ कम्पेंसेशन दिलाने के लिये क्या प्रयत्न किया है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : ज़िम कोलियरी में कर्मचारियों को रखा गया है, इस समय मैं उनका नाम देने में असमर्थ हूँ।

श्री राम नारायण शर्मा : ए० सी० सी० की दूसरी माइन नहीं है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : मुझे बताया गया है कि वहाँ फिनलान्ड 300 आदिमियों को काम दिया जाने वाला है। जहाँ तक आग लगने का प्रश्न है, उसकी एन्क्वायरी कराई जाती है और जो दोषी पाया जाता है, उसको दंडित किया जाता है। इस सम्बन्ध में जो नियम बनाये गये हैं उनका पालन करना माइनिंग-औरर के लिए जरूरी है। अगर कोई उन नियमों का पालन न करने का दोषी होगा, तो वह दंडित किया जायेगा। ले-आफ पीरियड में कर्मचारियों की वे की व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

Headquarters Allowance to I. F. S. Officer

*500 SHRI SHASHI BHUSHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the officers of IFS (A) get Headquarters Allowance while they are posted on duty in Delhi ;

(b) whether this Headquarters Allowance is denied to the members of IFS (B) , and

(c) if so, the reasons therefor and the measures proposed to be adopted by Government to grant the said allowance to the members of IFS (B) also ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : No Headquarters